

निर्णय बड़जलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या - 31/2013(रे0वाद)

दायर दिनांक - 05/03/2013

निर्णय दिनांक - 28/01/2026

अनवान

1. भंवरलाल पिता चुन्नीलाल जाति खटीक निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

-प्रतिवादी

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से- पैरोकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी को दिनांक 19/06/1992 की ग्राम अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज०) की बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 1 में 2 बीघा (दो बीघा) भूमि राजस्थान राज्य द्वारा सरकारी गठित आवंटन कमेटी (समस्या समाधान शिवीर) में जिसके अध्यक्ष श्रीमान् उप जिलाधिश महोत्तय भीम राज० होकर गैर खातेदारी हक से आवंटन हुई और जिसको कब्जों चांदी को राज्य सरकार द्वारा मोके पर सुपुर्द कर दिया गया और तब से लगायत अब तक इस वाद की उक्त भूमि पर कब्जा वादी का निरन्तर व निर्विधने कैंप से बराबर चला आया है और वादी ने इस भूमि को जो बेरान थी को करीब 1,00,000/- रुपये एक लाख रुपये खर्च कर आबाद की है। जिससे यह जमीन वादी के नाम पर गैर बातेदारी हक से दर्ज किये जाने के बजाय खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा का यह वाद प्रस्तुत है। वादी को जो इस वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित जमीन राज्य सरकार (राज०) से नियमानुसार गठित कमेटी में आवंटन हुई और इसका मुकदमा नम्बर 58/92 माननीय उपखण्ड अधिकारी भीम जिला राजसमन्द (राज०) के यहा दायर हुआ है। नियमानुसार वादी को जो इस वाद की कलम संख्या की जमीन राजस्थान राज्य से आवंटन हुई है जो वादी के नाम पर सरकारी रेकॉर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी द्वारा एंव उप जिलाधिश महोत्तय भीम द्वारा खाते दर्ज करा देनी चाहिये थी लेकिन किसी तरह इस वाद से संबधित जमीन वादी के



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द,

खाते दर्ज नहीं हो पाई है और यह जमीन बिलानाम में ही चल रही है जिससे वादी को जो इस वाद की उक्त वर्णित जमीन राजस्थान राज्य से आवंटन हुई है और वो वादी के कब्जे कास्त में चली आई है जिसे वादी के नाम पर सरकारी रेकॉर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने के लिए यह वाद प्रस्तुत है। वादी ने इस दावे से पूर्व प्रतिवादी को एंव उप जिलाधीश महोदय भीम को इस वाद की जमीन वादी के नाम पर सरकारी रेकॉर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है किन्तु वादी के नाम पर जमाबंदी में इस वाद की जमीन खाते दर्ज नहीं हो पाने से वादी को इस वाद के लिये विवश होना पडा है। वादी ने राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्री जिलाधीश महोदय राजसमन्द को धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का नोटिस इस वाद की जमीन वादी के नाम पर सरकारी रेकॉर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने की व्यवस्था के लिये दिनांक 26/07/2012 को रजिस्टर्ड एडी. दिया जो उन्हें दिनांक 29/07/2012 को मिल गया और इस नोटिस की मियाद दिनांक 28/09/2012 को समाप्त हो गई। फिर भी जिलाधीश महोदय राजसमन्द (राज०) ने यह जमीन वादी के नाम पर सरकारी रेकॉर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने की व्यवस्था नहीं की है जिससे भी वादी को इस वाद के लिये अन्तिम तोर पर विवश होना पडा है। इस वाद का अन्तिम कारण इस वाद की कलम संख्या 5 में वर्णित धारा 80 जा.दी. के रजिस्टर्ड नोटिस एडी दो माह की मियाद का दिनांक 26/07/2012 को राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि श्री जिलाधीश महोदय राजसमन्द को दिया गया जो उन्हें दिनांक 29/07/2012 को मिल गया व दिनांक 28/09/2012 को उस नोटिस मियादी दो माह की मियाद समाप्त हो गई फिर भी इस वाद की जमीन वादी के नाम पर उन्होंने (जिलाधीश महोदय राजसमन्द ने जमाबंदी में खाते दर्ज नहीं कराई। जिससे दिनांक 28/09/2012 को ग्राम अर्जुनगढ तहसील देवगढ में पैदा हुआ है। इस वाद की भूमि जो ग्राम अर्जुनगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज०) में स्थित है व वादी वहाँ का स्थाई निवासी है और अतिवादी भी जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है और उनका कार्यालय देवगढ में ही स्थित है जिससे इस वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय आपको है। वादी की निम्न प्रार्थना है कि इस वाद की कलम संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 1 बिलानाम वाकें ग्राम अर्जुनगढ तहसील देवगढ राजस्थान में जो 2 बिघा जमीन राजस्थान राज्य से वादी को दिनांक 19/06/1992 को नियमानुसार आवंटन होकर वादी को कब्जे में चली आई है उस वादी के कब्जे की जमीन का प्रकरण संख्या 59/12 उपखण्ड अधिकारी महोदय भीम जिला राजसमन्द (राज०) में दायर होने की घोषणा कराई जावे। वादी ने जो इस वाद की उक्त वर्णित भूमि जो गैर खातेदारी हक से आवंटन हुई थी जिसे एक लाख रुपया खर्च कर इस बेरान जमीन को आबाद की है जो वादी के कब्जे की चली आई है जो मोक़े पर वादी के कब्जे की जमीन है उसे वादी के नाम पर जमाबंदी में खातेदार के हक से दर्ज कराई जाने की भी घोषणा कराई जावे। व इसका आदेश प्रतिवादी के नाम पर जारी कराया जावे। वादी की प्रार्थना है कि इस वाद की जमीन किसी तरह वादी के नाम पर



28/1
सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला राजसमन्द 2

खातेदारी हक से दर्ज नहीं होने की हालत में वादी के नाम पर इस वाद की जमीन गैर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा करा वादी के खाते जमीन दर्ज कराई जावे। अन्य जरूरी दाद कानुनी रूप से जो वादी को मिल सकती हो वो भी दिलाई जावें। इस प्रकरण का वादी का होने वाला हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

मामलें में प्रस्तुत दावा एवं जवाब दावें के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :-

1. आया कि ग्राम अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के आराजी संख्या 01 में से 02 बीघा भूमि वादी को आवंटित हुई जिसे वादी गैरखातेदारी हक से दर्ज कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2. आया वादी वक्त आवंटन से निरन्तर काबिज हो काबिल काशत है।

जिम्मे वादी

3. आया उक्त वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित वादी के नाम पर कोई नामान्तरण दर्ज नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

4. आया आराजी संख्या 01 पर वादी का कब्जा नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

वादी एवं प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे उभय पक्ष के साक्ष्य बंद किये गए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निर्णय करने से पूर्व राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा।

उक्त नियमों में नियम 15 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

15. Order of Allotment. -

(1) As soon as an order of allotment is passed, the Sub-Divisional Officer shall-

(a) give necessary information to the Patwari then and there if the Patwari is present on the spot; and

(b) direct the Patwari to make over possession of the allotted land to the allottee forthwith;



20/13
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द 3

(c) where the allottee is not actually given possession of the allotted land within one month from the date of the order of allotment he shall apply to the Collector who shall enforce the order unless it is stayed by a competent authority.

(2) An order to allotment shall be in Form V and a copy of the same together with a trace of the land, shall be given to the allottee.

(3) Physical possession of the allotted land shall be delivered to the allottee within fifteen days from the date of allotment and, thereupon, a sanad shall be issued in Form VI to the allottee 15[on payment of a fee of rupees one hundred for irrigated land and rupees fifty for unirrigated land] to be credited to Head "IX-Land Revenue (i) Miscellaneous-'VII-Miscellaneous.

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने से वादी का साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा जिससे प्रकरण में उनकी साक्ष्य बन्द की गयी।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा जो दस्तावेज आवंटन आदेश के रूप में अभिलिखित कर प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः वह आवेदन पत्र है जिसमें तहसीलदार, विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और उसी में यह अंकन है कि भूमि आवंटन की गई है लेकिन आवंटन से संबंधित नियम 15 के संदर्भ में स्पष्ट Form V में आवंटन आदेश एवं Form VI में निश्चित शुल्क जमा कर सनद जारी की जाती है। यह दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आवंटन की प्रक्रिया को वैधानिक स्थिति प्रदान करते हैं लेकिन इस प्रकार के दोनों दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण संभवतः गैर खातेदारी का नामान्तरण नहीं किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है तथापि आवंटन आदेश के अनुपालन का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :-

1. उक्त तनकी संख्या 01 जिम्में वादी होकर वादी ने अपनी तनकीयात के समर्थन में गवाह एवं साक्ष्य पेश नहीं किए। वादी द्वारा आवंटन आदेश के संबंध में वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं करने वादी उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित कि जाती है।
2. उक्त तनकी संख्या 02 जिम्में वादी होकर तनकी संख्या 01 के अनुसरण में वादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस व स्वतंत्र साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत



10/10
सहायक कलेक्टर 4
देवगढ़, जिला राजसमन्व

कब्जा के संबंध में दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जिससे जिससे उक्त तनकी सिद्ध हो सकें। अतः तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित कि जाती है।

3. उक्त तनकी संख्या 03 जिम्मे प्रतिवादी होकर पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार वादी के पक्ष में आवंटन आदेश संबंधित नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
4. उक्त तनकी संख्या 04 जिम्मे प्रतिवादी होकर तनकी संख्या 03 के अनुसरण में पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 372 के सेटलमेन्ट अनुसार बने नवीन आराजी संख्या पर वादी का कब्जा नहीं है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वास्तविक एवं सतत कब्जा सिद्ध करने हेतु कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी अधिवक्ता केवल आवंटन आदेश का प्रस्तुत किया जाना खातेदार अधिकारी अथवा कब्जा सिद्ध नहीं करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 एवं 102 के अनुसार जो पक्ष किसी अधिकार का दावा करता है, उसे उसका प्रमाण देना अनिवार्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 91 के अन्तर्गत खातेदार अधिकार की घोषणा तभी की जा सकती है जब वादी आवंटन की वैधता, कब्जा अधिकार का क्रियान्वयन साक्ष्य द्वारा सिद्ध करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप मैं यह पाता हूँ कि वादी अपने वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है। इसलिए दावा वादी डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

—::आदेश::—

अतः वादी का वाद वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88-89-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (अधिकारी)
देवगढ़ जिला राजसमन्व

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- मोहकम सिंह सिनसिनवार आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :-31/2013

अनवान

1. भंवरलाल पिता चुन्नीलाल जाति खटीक निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

-प्रतिवादी

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से- पैरोकार सरकार

दावा वादी डिक्री किया जाता है अतः वादी का वाद वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88-89-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास
सुनाया गया।



21/10
(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़ जिला राजसमन्द